भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 785

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022 / 21 अग्रहयण, 1944 (शक)

ई-कॉमर्स प्लेटफार्म

785. श्री फिरोज वरुण गांधी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में वर्ष 2022 में ट्विटर, मेटा, अमेजन और सिस्को जैसी वैश्विक कंपनियों द्वारा छंटनी किए गए कर्मचारियों की संख्या का लेखा-जोखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में देश में छंटनी के संबंध में ई-कॉमर्स प्लेटफार्म अमेजन को तलब किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वे अमेजन द्वारा स्वैच्छिक पृथक्करण नीति को समाप्त किए जाने के बारे में आम सहमति पर पहुंचने में सफल रहे?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कामबंदी सहित रोजगार और छंटनी एक नियमित घटना है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कामबंदी और छंटनी से संबंधित मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं, जो कामबंदी के विभिन्न पहलुओं और कर्मकारों की छंटनी से पहले की शर्तों को भी विनियमित करता है। आईडी अधिनियम के अनुसार, 100 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने, छंटनी या कामबंदी करने से पहले समुचित सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके अलावा, किसी भी छंटनी और कामबंदी को अवैध माना जाता है जो आईडी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया जाता है। आईडी अधिनियम में मुआवजे हेतु काम से रोके गए और छंटनी किए गए कर्मकारों के अधिकार का भी प्रावधान किया गया है और इसमें छंटनी किए गए कर्मकारों के पुनर्नियोजन का भी प्रावधान है। आईडी अधिनियम में सीमांकित उनके संबंधित अधिकार-क्षेत्र के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर्मकारों की समस्याओं का समाधान करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करती हैं। केंद्र सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों में, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) को अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने और कामगारों के हितों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है, जिसमें कामबंदी और छंटनी और उनकी रोक से संबंधित मामले शामिल हैं। आईटी, सोशल मीडिया, एडु टेक फर्मों और संबंधित क्षेत्रों में बहु-राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों के संबंध में अधिकार-क्षेत्र

संबंधित राज्य सरकारों के पास है। इन क्षेत्रों के संदर्भ में कामबंदी और छंटनी पर केंद्रीय स्तर पर कोई डेटा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ): अमेज़न इंडिया ने सूचित किया है कि उनकी वार्षिक प्रचालन योजना समीक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में वे अपने प्रत्येक व्यवसाय को देखते हैं और वे परिवर्तन में विश्वास करते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए, वर्तमान मैक्रो-इकोनॉमिक माहौल के दृष्टिगत उनकी कुछ टीमें समायोजन कर रही हैं, जिसमें कुछ टीमों में कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण कार्यक्रम (वीएसपी) का विकल्प चुनने का अवसर देना शामिल है। वीएसपी एक पूरी तरह से स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसके तहत कर्मचारी उचित विच्छेद पैकेज प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं। उन्होंने सूचित किया है कि वे अपने कर्मचारियों को वीएसपी चुनने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। अमेज़ॅन इंडिया ने सूचित किया कि वीएसपी के लिए चयन करने का निर्णय 100% स्वैच्छिक है और वे कर्मचारियों को एक विस्तारित विंडो की पेशकश कर रहे हैं, यदि वे फिर से आने और/या अपने निर्णय को रद्द करने का विकल्प चुनते हैं। अमेज़न इंडिया ने आगे बताया कि यदि कोई कर्मचारी वीएसपी का विकल्प नहीं चुनता है तो इस निर्णय के कारण उसके रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

*****